



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2018/भाद्र 1, 1940  
No. 321] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2018/BHADRA 1, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 10 अगस्त, 2018

**सं. टीएमपी/22/2018-वीपीटी.**—तेलंगाना राज्य तथा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 2003 की 9088, 9585, 20005 और 26404 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार तथा निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/22/2018-वीपीटी

- (i) श्री लक्ष्मी मरीन प्रोड्यूसर्स लि.,
- (ii) एस.बी.एस. मरीन एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.,
- (iii) मै. कंचन गंगा सी फूड्स लि.,
- (iv) श्री साई कृष्ण एग्रोकोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.,
- (v) मै. गोपाल कृष्ण इंटरप्राइजेज,
- (vi) मै. श्री गोपाल कृष्ण एसोसिएशन,
- (vii) डॉ. वाई.जी.के. मूर्ति और
- (viii) मै. गोवा ऑर कैरियर्स

याचिकाकर्ता

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

**आदेश**  
**(जुलाई, 2018 के 31वें दिन पारित)**

यह मामला रिट याचिका सं. 2003 के 9088, 9585, 20005 और 26404 पर संयुक्त निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में तेलंगाना राज्य तथा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री पी. केशव राव द्वारा दिए गए निदेश से आया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय में इस प्राधिकरण तथा अन्य के विरुद्ध विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई निम्नलिखित रिट याचिकाओं के संदर्भ में हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय में श्री के. लक्ष्मण, भारत के सहायक महाधिवक्ता (एसएसजीआई) से 19 मार्च 2018 को एक पत्र दिनांक 24 फरवरी 2018 प्राप्त हुआ था।

- (i) भारत मरीन एक्सपोर्ट्स (याचिकाकर्ता सं. 1), सत्यसाई मरीन प्राइवेट लि. (याचिकाकर्ता सं. 2) और श्री लक्ष्मी मरीन प्रोड्यूसर्स लि. (याचिकाकर्ता सं. 3) द्वारा भारत संघ, कृषि मंत्रालय एवं भूतल परिवहन मंत्रालय (प्रतिवादी सं. 1 और 2), टीएमपी (प्रतिवादी सं. 3), विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) (प्रतिवादी सं. 4) और मै. एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 5) के विरुद्ध दायर रिट याचिका सं. 2003 की 9088  
(रिट याचिका जहाँ तक याचिकाकर्ता सं. 1 अर्थात् भारत मरीन एक्सपोर्ट्स और याचिकाकर्ता सं. 2 अर्थात् सत्यसाई मरीन प्राइवेट लि. का संबंध है, इसे न्यायालय आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2008 के अनुसार वापिस लिया गया मानकर खारिज किया गया है।)
- (ii) एस.बी.एस. मरीन एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि. (याचिकाकर्ता सं. 1) और मै. कंचन गंगा सी फूड्स लि. (याचिकाकर्ता सं. 2) द्वारा भारत संघ (प्रतिवादी सं. 1 और 2), टीएमपी (प्रतिवादी सं. 3), वीपीटी (प्रतिवादी सं. 4) और मै. एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 5) के विरुद्ध दाखिल रिट याचिका सं. 2003 का 9585
- (iii) श्री साई कृष्णा एग्रीकोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. (याचिकाकर्ता सं. 1), मै. गोपाला कृष्ण इंटरप्राइजिज (याचिकाकर्ता सं. 2), मै. श्री गोपाल कृष्ण एसोसिएशन (याचिकाकर्ता सं. 3) और डॉ. वाई.जी.के. मूर्ति (याचिकाकर्ता सं. 4) द्वारा भारत संघ (प्रतिवादी सं. 1 और 2), टीएमपी (प्रतिवादी सं. 3), वीपीटी (प्रतिवादी सं. 4) और मै. एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 5) के विरुद्ध दायर रिट याचिका सं. 2003 की 20005
- (iv) मै. गोवा ऑर कैरियर्स द्वारा भारत संघ (प्रतिवादी सं. 1 और 2), टीएमपी (प्रतिवादी सं. 3) और वीपीटी (प्रतिवादी सं. 4 और 5) के विरुद्ध दायर रिट याचिका सं. 2003 की 26404

3.1. एसएसजीआई ने उक्त पत्र में सूचित किया था कि उपर्युक्त याचिकाएं 20 दिसम्बर 2017 को हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई थीं और संबद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद, माननीय न्यायालय ने पोट प्रभारों की वृद्धि के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उपर्युक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए प्रतिवादी सं. 3 और 4 को निदेश देते हुए रिट याचिकाओं का निपटान किया था और आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त आदेश जारी करने का निदेश दिया था।

3.2. एसएसजीआई ने, अपने उक्त पत्र के साथ, उपर्युक्त याचिकाओं में माननीय श्री जस्टिस पी. केशव राव के माननीय उच्च न्यायालय संयुक्त आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की मूल प्रमाणित प्रति अग्रेषित की थी। आदेश के लागू किए जाने वाले भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

- “6. प्रकथनों का अवलोकन — याचिकाकर्ता। उस तरह बन जैसे यह हो सकता है, यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि याचिकाकर्ताओं ने पोट प्रभारों को कम करने और 16-05-2001 से पहले मौजूद केवल पुरानी दरों जमा 15 प्रतिशत वृद्धि जिसे याचिकाकर्ताओं और अन्य ने 08-12-2000 को हुई बैठक में स्वीकार किया था, को जारी रखने के लिए अनुरोध करते हुए निदेशक, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास अर्थात् प्रतिवादी 3 और 4 को अभ्यावेदन दिनांक 09-12-2000, 19-07-2001, 26-07-2001 और 19-08-2001 दाखिल किए थे। अतः, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वत अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि प्रतिवादी 3 और 4 को उक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उपर्युक्त आदेश पारित करने का निदेश दिया जाए।
7. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वत अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों और जवाब में दाखिल किए गए शपथ में दिए गए दृढ़ कथनों के मद्देनजर, इस न्यायालय को यह उपर्युक्त महसूस हुआ कि पोट प्रभारों की वृद्धि से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उपर्युक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त आदेश पारित किए जाने के लिए प्रतिवादी 3 और 4 को निदेश दिया जाए।
8. उपर्युक्त निदेशों के साथ, सभी चार रिट याचिकाओं का निपटान किया गया है। अब लागत से संबंधित कोई आदेश नहीं होगा।
9. इन रिट याचिकाओं में लंबित विविध याचिकाएँ, यदि कोई हों, बन्द हो जाएंगी।”

3.3. इस प्रकार, संक्षेप में, माननीय एकल न्यायाधीश ने पोट प्रभारों की वृद्धि के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 10 जुलाई, 2001, 26 जुलाई 2001 और 19 अगस्त 2001 पर विचार करने और आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर उचित आदेश जारी करने के लिए प्रतिवादी सं. 3 (टीएमपी) और प्रतिवादी सं. 4 (वीपीटी) को निदेश जारी किया है।

3.4. माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश कार्यालय में 19 मार्च 2018 को प्राप्त हुआ था। इसलिए, उस तारीख से 3 महीने 18 जून 2018 को समाप्त हो गए थे जिस तारीख तक इस प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किया जाना है।

4. याचिकाकर्ताओं और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्री (एआईएफआई) द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों की जाँच करने की कार्यवाही से पूर्व, इस मामले के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताना प्रासंगिक होगा। रिट याचिका सं. 2003 की 9088 और रिट याचिका सं. 2003 की 9585 के संदर्भ में, मामले का निम्नलिखित संक्षिप्त इतिहास नीचे दिया गया है:—

- (i) इस प्राधिकरण ने वीपीटी दरमान का सामान्य संशोधन अनुमोदित करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/103/99-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 पारित किया था। उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने फिशिंग पोतों के लिए लागू सभी प्रभारों पर 100 प्रतिशत प्रशुल्क वृद्धि अनुमोदित की थी। यह निर्णय फिशिंग पोत के लागत विवरण जो वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए 239 प्रतिशत का घाटा प्रदर्शित कर रहा था, के आधार पर लिया गया था। तथापि, प्रशुल्क वृद्धि

वीपीटी द्वारा प्रोद्भूत परिचालन व्यय को कवर करने के लिए केवल 100 प्रतिशत की सीमा तक सीमित किया गया था। फिशिंग पोतों के लिए एकसमान दर वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित समूहन के आधार पर अनुमोदित की गई थी। (आदेश का पैरा 21 (vi) एवं (viii))

- (ii) तत्पश्चात्, वीपीटी ने आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (एपीएमएफबीओए) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्री (एआईएफआई) के अभ्यावेदनों के आधार पर, इस प्राधिकरण से फिशिंग पोतों के पूर्व वर्गीकरण को बहाल करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह स्वीकार किया गया था कि फिशिंग पोत की विभिन्न श्रेणियों को इकट्ठा करने से कम एनआरटी की मेकेनाइज्ड नावों और फिशिंग पोतों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। तदनुसार, इस प्राधिकरण को फिशिंग पोतों के लिए पहले निर्णीत प्रशुल्क के ऊर्ध्वमुखी संशोधन के प्रतिशत की समीक्षा करने के लिए कोई औचित्य दिखाई नहीं दिया था।
- (iii) भारत मरीन एक्सपोर्ट्स ने टीएमपी, वीपीटी और अन्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका सं. 2003 का 9088 दाखिल किया था। मै. एसबीएस मरीन एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड और मै. कंचन गंगा सी फूड्स लिमिटेड ने भी इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में इसी तरह की रिट याचिका सं. 2003 का 9585 दायर की थी।

5.1. रिट याचिका सं. 2003 की 20005 और 2003 की 26404 का अवलोकन करने पर यह देखा गया है कि माननीय न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं अर्थात् 2003 की 9088, 9585, 20005 और 26404 का निपटान करते हुए संयुक्त आदेश पारित करते समय इस प्राधिकरण तथा वीपीटी को निर्देश दिया है कि पोत प्रभारों की वृद्धि से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 और 19 अगस्त 2001 पर विचार किया जाए और आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश पारित किए जाएं।

5.2. इस संबंध में, माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश में बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने टीएमपी और वीपीटी को पोत प्रभारों की वृद्धि से संबंधित अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 और 19 अगस्त 2001 दिये थे, यह बताया जाता है कि हमें याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 और 19 अगस्त 2001 सीधे प्राप्त नहीं हुए थे। ऐसे अभ्यावेदनों को डल्यू.पी. सं. 2003 की 9585 और 9008 के हिस्से के रूप में किसी में भी शामिल नहीं किया गया है। तथापि, उस अवधि से संबंधित वीपीटी की सामान्य संशोधन फाइल का अवलोकन करने पर, यह देखा गया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) जो फिशिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, ने अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 और आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (एपीएमएफबीओए) ने अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 (यह 19-08-2001 नहीं है) दाखिल किए थे जिन्हें वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा अग्रपिछित किया था।

**क. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) का अभ्यावेदन और टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 का प्रासंगिक भाग**

6.1. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000 टीएमपी को संबोधित किया गया है। उक्त अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

- (i) एआईएफआई ने वीपीटी, विशाखापत्तनम में 8 दिसम्बर 2000 को हुई बैठक (संयुक्त सुनवाई) में भाग लिया था। उस दिन हुई चर्चाओं के अनुसार, एआईएफआई ने निवेदन किया था कि वे अध्यक्ष के प्रस्तावों के अनुसार मेनेजमेंट ऑफ फिशिंग हारबर स्लिपवे कॉम्प्लेक्स को अपने हाथ में लेने के इच्छुक हैं।
- (ii) फिशिंग हारबर में स्लिपवे कॉम्प्लेक्स और ड्राइ-डॉक के प्रभारों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि के लिए वीपीटी का प्रस्ताव उचित नहीं है और एआईएफआई ने इन प्रभारों की वृद्धि को वीपीटी के अन्य प्रभारों के बराबर जिनमें 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था, करने का अनुरोध किया था।

6.2. इस संबंध में, एआईएफआई का अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000 उपर्युक्त पैरा 6.1 में दिया गया है, यह कहना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 में वीपीटी के एसओआर के सामान्य संशोधन में पैरा 21(viii) में विचार किया गया था। उक्त आदेश का प्रासंगिक पैरा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“(viii). लौह अयस्क प्रहस्तन गतिविधि और फिश हारबर के मामले में, पत्तन द्वारा प्रस्तावित संशोधित दरें लागू किए जाने के बाद भी परिचालनात्मक नुकसान उठाता रहेगा। पत्तन ने बाहरी हारबर की शुरुआत के समय से लौह अयस्क के प्रहस्तन के लिए कमी भी रेंयूनिरेटेड दरें प्राप्त नहीं की हैं। वीपीटी के अनुसार, हालांकि आंतरिक हारबर लौह अयस्क निर्यातों का प्रहस्तन करने में समर्थ नहीं था, बाहरी हारबर सुविधा निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े पोतों का प्रहस्तन करने के लिए सृजित की गई थी। विभिन्न विचारों के लिए, पत्तन को उसकी लागत के आधार पर दरों में वृद्धि करने के लिए पूर्वकाल में अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा, पूर्वानुमानित यातायात भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, अब बढ़ रही घाटा स्थिति मुख्यतः पूर्वकाल में (नहीं) की गई (उचित) कार्रवाईयों के संचयन के कारण है। प्रशुल्क सुधार एक ही बार में नहीं किए जा सकते। इसके अलावा, इस मामले में, वीपीटी को यातायात लाइवर्जन की भी आशंका है, यदि दरें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिससे पत्तन की समस्या केवल बढ़ेगी ही। ऐसी स्थिति में, अन्य गतिविधियों से अधिशेष को पूरा करने के लिए इस गतिविधि के अधीन कवर नहीं किए गए परिचालनात्मक व्यय को छोड़ते हुए, पत्तन द्वारा प्रस्तावित स्तर पर दरों में वृद्धि अनुमोदित की गई है। इसी तरह, फिश हारबर के लिए मौजूदा दरों में भी 100 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी भले ही यह सम्पूर्ण परिचालनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो। चूंकि इस स्तर से अधिक किसी वृद्धि से उपयोगकर्ताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा, इसलिए वृद्धि को 100 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। यहां दोबारा, परिचालनात्मक नुकसान को अन्य गतिविधियों के अधिशेष से पूरा किया जाना है। फिशिंग हारबर के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) द्वारा दी गई ऑफर पूरी तरह से संदर्भ से परे है। अब संशोधित किए जा रहे दरमान वीपीटी द्वारा प्रोद्भूत लागत के संदर्भ में हैं। यदि (वीपीटी से इतर) प्रबंधन में कोई बदलाव किया जाता है, यह कहना व्यर्थ है कि फिशिंग हारबर के लिए प्रशुल्क वीपीटी के दरमान से हटा दिए जाएंगे। खैर, प्रबंधन में बदलाव का मुद्दा इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाला मुद्दा नहीं है। एआईएफआई फिशिंग हारबर को अपने हाथ में लेने के लिए अपने प्रस्ताव के साथ उपयुक्त मंच पर जा सकता है।”

**ख. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) के अभ्यावेदन दिनांक 19 जुलाई 2001 और 26 जुलाई 2001**

7. कृषि मंत्रालय को पृष्ठांकित प्रतिलिपि के साथ टीएमपी को संबोधित एआईएफआई से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 19 जुलाई 2001 इस प्राधिकरण द्वारा पारित और 4 जून 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 के बाद प्राप्त हुआ था। एआईएफआई से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 26 जुलाई 2001 वीपीटी को संबोधित था और इसकी एक प्रति टीएमपी को पृष्ठांकित की गई थी जिसमें एआईएफआई के पत्र दिनांक 19 जुलाई 2001 का उल्लेख किया गया था और इस प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था कि दरों को 100 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करते हुए तत्काल आदेश दिनांक 16 मई 2001 संशोधित किया जाए। दोनों अभ्यावेदनों में किए गए निवेदन एकसमान हैं। उपर्युक्त पत्रों में एआईएफआई द्वारा कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i) 8 दिसम्बर 2000 को वीपीटी में (वीपीटी के एसओआर के सामान्य संशोधन पर) हुई संयुक्त सुनवाई और एआईएफआई पत्र दिनांक 9 दिसम्बर 2001 का उल्लेख करते हुए, एआईएफआई ने कहा था कि वे इस प्राधिकरण द्वारा 16 मई 2001 को पारित और राजपत्र सं. 143 द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 4 जून 2001 को अधिसूचित आदेश में स्लिपवे कॉम्पलेक्स और शुष्क गोदी दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि से संबंधित सूचना प्राप्त करके हैरान और सदमे में हैं।
- (ii) 8 दिसम्बर 2000 को हुई बैठक के दौरान अनुरोध किए जाने के बावजूद एक ही बार में 100 प्रतिशत तक असामान्य तौर से पत्तन प्रभारों में वृद्धि का यूनिटेटरल निर्णय लेना उचित नहीं है। एआईएफआई इस यूनिटेटरल निर्णय पर खेद व्यक्त करती है जिससे निश्चित रूप से फिशिंग इंडस्ट्री हैम्पर होगी जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है।
- (iii) विशाखापत्तनम फिशिंग हारबर गहरे समुद्र वाले फिशिंग पोतों के कार्य के लिए भारत में विकसित एकमात्र हारबर है। इस हारबर का निर्माण कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्माण करवाया गया था और फिशिंग हारबर का प्रबंधन वीपीटी को सौंपा गया था।
- (iv) पत्तन प्रभारों की सामान्य वृद्धि अधिकांश सेवाओं के लिए केवल 10 से 15 प्रतिशत है जबकि 8 दिसम्बर 2000 को हुई बैठक में 15 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने की एआईएफआई की अपील पर विचार किए बिना फिशिंग हारबर सेवा प्रभारों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गई।
- (v) दि इंडियन डीप सी फिशिंग इंडस्ट्री बड़े हुए डीजल तेल, स्पेयर पार्ट्स तथा रखरखाव प्रभारों के कारण बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। इंडस्ट्री की ताकत 160 से 90 पोत तक गिर गई है। शेष 70 पोतों को परिचालनों की अनुपलब्धता के कारण कबाड़ में बदल दिया गया है। फिशिंग हारबर एक राष्ट्रीय संपत्ति है और वास्तव में एआईएफआई ने स्लिपवे तथा शुष्क गोदी सहित फिशिंग हारबर प्रबंधन एआईएफआई, इंडियन डीप सी फिशिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था, को सौंपने के लिए पत्र लिखे हैं। इसलिए, एआईएफआई अनुरोध करता है कि फिशिंग हारबर सेवाओं को पत्तन सेवाओं और विशाखापत्तनम फिशिंग हारबर के साथ नहीं जोड़ा जाए क्योंकि यह कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय परिसंपत्ति है।
- (vi) फिशिंग हारबर के रखरखाव का कार्य वीपीटी को सौंपा गया है। व्ययों के संबंध में वीपीटी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन तथा 239 प्रतिशत घाटा दर्शाना फिशिंग इंडस्ट्री को स्वीकार्य नहीं है। कृपया फिशिंग हारबर का प्रबंधन कार्य एआईएफआई को सौंपा जाए और एआईएफआई 16 मई 2001 दरों से पहले की दरों पर इसे मुनाफे में पहुंचा देंगे। इसी बीच, एआईएफआई ने 16 मई 2001 से पहले की मौजूद पुरानी दरों की वसूली करने और बढ़ाई गई दरों को तब तक लंबित रखने का अनुरोध किया था जब तक विशाखापत्तनम फिशिंग हारबर हस्तांतरित किए जाने का मामला हल नहीं हो जाता।

**ग. आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (एपीएमएफबीओए) का अभ्यावेदन दिनांक 18-08-2001 (सांसद पत्र दिनांक 19-08-2001):**

8.1. न्यायनिर्णय में उल्लिखित अभ्यावेदन दिनांक 19 अगस्त 2001 के संबंध में, यह कहना है कि वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा कहा है कि फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़ी विभिन्न एसोसिएशनों ने फिशिंग पोतों के लिए निर्धारित प्रशुल्क पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करते हुए सांसद (एम.पी.) (लोक सभा) के माध्यम से अभ्यावेदन दिनांक 19 अगस्त 2001 प्रस्तुत किया था। वीपीटी ने अपने उक्त पत्र के कवर के अधीन एम.पी. को संबोधित आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (एपीएमएफबीओए) के अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 की प्रति, वीपीटी को संबोधित डीप सी ट्रॉलर्स ऑनर्स एसोसिएशन (डीएसटीओडब्ल्यूए) के अभ्यावेदन दिनांक 8 अगस्त 2001 की प्रति, और वीपीटी को संबोधित एआईएफआई का अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 अग्रेषित किया था।

8.2. एपीएमएफबीओए के अभ्यावेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2001 में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i) हम रु. 229.30 प्रति माह प्रति बोट बर्थ प्रभारों की अदायगी कर रहे हैं, जबकि हाल ही में विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण ने दरों में असामान्य ढंग से वृद्धि की है, अभियंत्रित फिशिंग नावों पर बर्थ प्रभार ऐसी उच्च दरों पर अदायगी करना बहुत ही असंभव है। विवरण नीचे दिए गए हैं:-

मद	पुरानी दरें	नई दरें
घाटशुल्क	रु. 53.80	रु. 1,075.00
पत्तन देयताएं	शून्य	143.50 नए शामिल
बर्थ प्रभार	5.50 से 20 टन प्रतिदिन तक	9.90 से 10 टन तक
केवल निवल टनभार आधार पर गणना किए जाने वाले बर्थ प्रभार।		14.85 से 15 टन तक
		17.82 से 18 टन तक
		18.81 से 19 टन तक
पानी प्रभार	रु. 5.00	81.40 प्रति 1000 लिटर
डीजल पर लेवी	0.04	0.08 + रु. 10/- के.एल.

- (ii) पुरानी दरों पर हम रु. 229.30 प्रति माह अदायगी कर रहे हैं। नई दरों पर हमें प्रतिमाह रु. 2069.00 की अदायगी करनी होगी। वर्तमान में, फिशिंग इंडस्ट्री बड़ी हुई डीजल दरों तथा अन्य मदों के कारण बहुत बीमार हालत में है। जबकि प्रॉन की दरों में बहुत अधिक गिरावट आई है। उपर्युक्त स्थिति के कारण, अधिकांश नाव मालिक अपनी फिशिंग नावें नहीं चला रहे हैं।
- (iii) उपर्युक्त के मद्देनजर, यह हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारी बहुत ही वास्तविक समस्या पर विचार करें और गरीब मछुआरों नाव स्वामियों के लिए पुरानी दरों को जारी रखा जाए।

9.1. अभ्यावेदन दिनांक 26 जुलाई 2001 हमारे पत्र दिनांक 9 अगस्त 2001 द्वारा वीपीटी को अग्रपिछित किया गया था और वीपीटी से इसकी जाँच करने तथा अपनी टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया गया था।

9.2. प्रतिसाद में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा और सांसद द्वारा अग्रपिछित एएमएफबीओए के अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणियाँ भेजी थीं:-

- (i) प्रति-सहायिकीकरण के साथ डिस्पेंस करने की नीति से सामंजस्य बैठाने हुए, पल्लन ने लागत केन्द्र 'फिश हारबर' के लिए लागत विवरण द्वारा दर्शाये गए 239 प्रतिशत घाटे को पूरा करने के लिए 100 प्रतिशत तक फिशिंग पोतों के लिए प्रभारों में वृद्धि पर विचार किया था; और, फिशिंग पोतों को वाणिज्यिक पोतों से सहायिकी के प्रवाह को भी रोका था।
- (ii) पल्लन म्यूनिसिपल कारपोरेशन से औद्योगिक दरों पर पानी खरीदता है और प्रासंगिक व्ययों के रूप में 2 प्रतिशत जोड़ने के बाद फिशिंग पोतों को इसकी आपूर्ति करता है; और, इसलिए, पानी के प्रभारों में भी वृद्धि की गई है। फिशरी इंडस्ट्री पानी की आपूर्ति के लिए दरों को लेकर सहज नहीं था। इसलिए, वीपीटी ने पानी की आपूर्ति रोकने का निर्णय लिया था और फिशिंग पोतों से अनुरोध किया गया था कि निजी परिचालकों से पानी की खरीद करें।
- (iii) अभियंत्रिकृत नावें, छोटे ट्रॉलरों और बड़े ट्रॉलरों को दरों का प्रस्ताव करते समय एक ही श्रेणी के अधीन समूहित किया गया था।
- (iv) फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़ी विभिन्न एसोसिएशनों अर्थात् आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, डीप सी ट्रॉलर ऑनर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्री ने फिशिंग पोतों के लिए निर्धारित प्रशुल्क पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करते हुए सांसद (लोकसभा) के माध्यम से 19 अगस्त 2001 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इन अभ्यावेदनों की प्रतियाँ वीपीटी द्वारा भेजी गई हैं।
- (v) शामिल मुद्दों की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद, वीपीटी ने महसूस किया था कि फिशिंग नावों के समूहन की सीमित सहनशीलता है और ट्रॉलरों के साथ कम लागत की उच्च सहनशीलता है और उच्च लागत किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा, अभियंत्रिकृत नावों के आगमनों की बारंबारता ट्रॉलरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जो अभियंत्रिकृत नावों के लिए संबंधित: कम दर के साथ औचित्य बताता है। इसलिए, वीपीटी ने पोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरों के अलग-अलग सैट अंगीकृत करना उचित महसूस किया है जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:
  - (क) अभियंत्रिकृत नावें
  - (ख) 14 एनआरटी तक के छोटे फिशिंग ट्रॉलर्स (22 जीआरटी तक)
  - (ग) 14 एनआरटी से अधिक के फिशिंग ट्रॉलर्स (22 जीआरटी से अधिक)
- (vi) फिशरी इंडस्ट्री द्वारा सामना किए जा रहे गंभीर संकट के मद्देनजर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैर-लाभकारी कीमतों के कारण, वीपीटी ने भी इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि सहानुभूति का नजरिया अपनाया जाए और अभियंत्रिकृत नावों के लिए प्रशुल्क पुनः निर्धारित किए जाएं।

9.3. वीपीटी पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 के आधार पर, इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 16 मई 2001 में फिशिंग पोतों के लिए अनुमोदित प्रशुल्क की समीक्षा करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 30 अगस्त 2001 पारित किया था। अगस्त 2001 के उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने फिशिंग पोतों के पूर्व वर्गीकरण को बहाल कर दिया था। तथापि, दरों में वृद्धि पूर्व-संशोधित दर पर 100 प्रतिशत बनाये रखी थी। आदेश दिनांक 30 अगस्त 2001 का प्रासंगिक पैरा 6(ii) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) ने फिशिंग नावों के लिए संशोधित दरमानों में निर्धारित पल्लन प्रभारों के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे थे। उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि वीपीटी के पूर्व-संशोधित दरमानों में, फिशिंग पोतों के लिए दरों को समूहित करते हुए तीन श्रेणियाँ अर्थात् (क) अभियंत्रिकृत फिशिंग नावें; (ख) फिशिंग ट्रॉलर्स (14 एनआरटी तक); और, (ग) फिशिंग ट्रॉलर्स (14 एनआरटी से अधिक) में निर्धारित किया गया था। तथापि, वीपीटी ने अपने प्रस्तावित दरमानों में इस वर्गीकरण को बनाये रखने का प्रस्ताव नहीं किया था। सामान्य संशोधन मामले में, वीपीटी ने फिशिंग ट्रॉलरों पर पूर्व-संशोधित प्रशुल्कों पर 100 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करते हुए फिशिंग पोतों की सभी श्रेणियों के लिए एकसमान प्रशुल्क प्रस्तावित किया था। इसके परिणामस्वरूप, अभियांत्रिक फिशिंग नावें फिशिंग ट्रॉलरों पर लागू प्रशुल्क वृद्धियों पर अनावश्यक बोझ रही हैं।*

*यह स्वीकार करना होगा कि प्रशुल्क प्रयोजनों के लिए फिशिंग पोतों की विभिन्न श्रेणियों को इकट्ठा करना एक गलती है, सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर कार्यवाही करते समय इस प्राधिकरण गहराई से समीक्षा नहीं की गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ध्यान अन्य प्रशुल्क मदों में लगा हुआ था जो पल्लन के राजस्व के नजरिये से महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, संयुक्त सुनवाईयों में भाग लेने वाले फिशरी उद्योग के प्रतिनिधियों ने प्रशुल्कों में 100 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध ही टिप्पणी की थी; परन्तु, वीपीटी द्वारा प्रस्तावित फिशिंग पोतों की विभिन्न श्रेणियों को इकट्ठा करने से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था।*

*वीपीटी ने भी अब यह निर्दिष्ट किया है कि प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए फिशिंग पोतों की सभी श्रेणियों को इकट्ठा करना औचित्यपूर्ण नहीं है। वीपीटी ने भी फिशिंग पोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न दरें बनाये रखने का अनुरोध किया था। वीपीटी द्वारा अब प्रस्तावित वर्गीकरण वही है जो इसके पूर्व-संशोधित दरमानों में उपलब्ध था।*

इस प्राधिकरण को लगता है कि फिशिंग पोतों के उस वर्गीकरण को बहाल करना तर्कसंगत और उचित होगा जो वीपीटी के पूर्व-संशोधित दरमानों में उपलब्ध था। पहले उपलब्ध फिशिंग पोतों के वर्गीकरण की बहाली से, उपर्युक्त उप-पैरा (i) में दिए गए कारणों से तत्संबंधित पूर्व-संशोधित दरों को भी 100 प्रतिशत तक संशोधित करना होगा।”

9.4. इस प्रकार, हमारे अभिलेखों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित अभ्यावेदनों पर प्रासंगिक प्रशुल्क आदेश जारी करते समय विचार किया गया था।

10. विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल रिट याचिका सं. 2003 की 9088, 9585, 20005 और 26404 के संदर्भ में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय के आदेश में, माननीय उच्च न्यायालय ने टीएमपी और वीपीटी को आदेश दिया है कि पोत प्रभारों की वृद्धि से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 और 19 अगस्त 2001 पर विचार किया जाए और आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं।

11.1. एकल पीठ न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में, वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा भेजे गए एआईएफआई के अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 और एआईएफआई तथा एपीएमएफबीओए दोनों के अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 को पृथक प्रशुल्क मामले के रूप में लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुपालन में हमारे पत्रों दिनांक 3 अप्रैल 2018 और 9 अप्रैल 2018 द्वारा याचिकाकर्ताओं को यह सूचित किया गया था और उपयोक्ता एसोसिएशनो अर्थात् एआईएफआई, एपीएमएफबीओए तथा डीएसटीओडब्ल्यूए को भी सूचित किया गया था जिनके अभ्यावेदनों का न्यायनिर्णय में उल्लेख किया गया था।

11.2. सारबद्ध करने के लिए, एआईएफआई तथा एपीएमएफबीओए द्वारा अपने अभ्यावेदन में कही गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

(i) एआईएफआई ने आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 में प्रदत्त 100 प्रतिशत वृद्धि के विपरीत 15 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ii) एपीएमएफबीओए ने फिशिंग गतिविधि के लिए 16 मई 2001 से पहले की मौजूदा दरों को जारी रखने का अनुरोध किया है।

12.1. हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार, वीपीटी को भी याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करना है। इसलिए, वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा अग्रेषित एआईएफआई के अभ्यावेदनों दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 तथा एआईएफआई तथा एपीएमएफबीओए दोनों के अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 की एक-एक प्रति यह अनुरोध करते हुए हमारे पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2018 द्वारा वीपीटी को अग्रेषित की गई थी कि 10 अप्रैल 2018 तक अपना प्रतिसाद भेजे।

12.2. वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2018 द्वारा कहा था कि फिशिंग ट्रॉलरों के लिए दरें वर्ष 2006, 2011 और 2016 में संशोधित की गई थीं जो याचिका दाखिल करने के बाद वीपीटी एसओआर की अद्यतन दरें हैं।

12.3. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 17 मई 2018 द्वारा आगे प्रतिसाद दिया था जिसके बारे में अनुवर्ती अनुच्छेद में बताया गया है।

12.4. समानान्तरतः, याचिकाकर्ताओं एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) और डीप सी ट्रॉलर ऑनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन को भी यह सूचित किया गया था कि उपर्युक्त याचिकाओं में हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री न्यायाधीश पी. केशव राव के उक्त संयुक्त आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के अनुपालन में, वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा टीएमपी को अग्रेषित एआईएफआई के अभ्यावेदनों दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 26 जुलाई 2001 और एआईएफआई एवं एपीएमएफबीओए दोनों के अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 को पुनः विचार के लिए लिया गया है और वीपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया जा रहा है।

12.5. याचिकाकर्ताओं अर्थात् मै. गोवा ऑर कैरियर्स, मै. श्री लक्ष्मी मरीन प्रोडक्ट्स लि. (एसएलएमपीएल), मै. कंचन गंगा सी फूड्स लि. तथा एस.बी.एस. मरीन एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि. को भेजे गए पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2018 और 9 अप्रैल 2018 डाक विभाग द्वारा 'अपर्याप्त पता', 'इस दरवाजा सं. में ऐसा कोई पता नहीं है', 'बन्द' और 'छोड़कर चले गए' आधार पर वापिस भेज दिए गए थे। इसलिए, वीपीटी से हमारे पत्रों दिनांक 19 अप्रैल 2018, 23 अप्रैल 2018 और 27 अप्रैल 2018 द्वारा सही पते के बारे में बताने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी द्वारा संप्रेषित पते पर याचिकाकर्ताओं को पत्र पुनः भेजे गए थे। तथापि, चूंकि याचिकाकर्ताओं को संबोधित पत्र डाक विभाग द्वारा पुनः वापिस कर दिया गया था, पत्र दिनांक 16 मई 2018 याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री वी.एस.आर. अंजनेयुलु को इस अनुरोध के साथ संबोधित किया गया था कि चार याचिकाकर्ताओं अर्थात् मै. श्री लक्ष्मी मरीन प्रोडक्ट्स लि., मै. गोवा ऑर कैरियर्स, मै. कंचन गंगा सी फूड्स लि. और एस.बी.एस. मरीन एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि. को डिलीवर नहीं हुए पत्र डिलीवर करवाने की व्यवस्था करें और उपर्युक्त याचिकाकर्ताओं के ईमेल आईडी, टेलीफोन नम्बर और फैक्स नम्बर के साथ सही पते अग्रेषित करें ताकि इसके बाद उनसे संवाद स्थापित कर सकें। समानान्तरतः, वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 16 मई 2018 द्वारा पुनः अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ताओं के सही पतों की जानकारी दें और याचिकाकर्ताओं को डिलीवर नहीं किए गए पत्र डिलीवर करवाये जाएं तथा उनकी पावती भी प्राप्त की जाए क्योंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के परिणामस्वरूप है। इसके अलावा, वीपीटी से भी उपर्युक्त याचिकाकर्ताओं के ईमेल आईडी, टेलीफोन नम्बर और फैक्स नम्बर के साथ सही पते अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया था ताकि इसके बाद उनसे संवाद स्थापित कर सकें।

12.6. इस संबंध में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 17 मई 2018 द्वारा सूचित किया था कि कुछ फर्मों के पत्र पंजीकृत डाक भेजने के बावजूद डिलीवर नहीं किए जा सके और इसके बारे में संयुक्त सुनवाई में सूचित कर दिया गया था।

13. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 25 अप्रैल 2018 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी और याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित निवेदन किए थे—

#### प्रियन फिशरीज और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) के सदस्य

- (i) पहले, वर्गीकरण ट्रॉलरों के लिए था जोकि अब प्रासंगिक नहीं हैं हम फिशिंग नावों के रूप में पंजीकृत हैं।
- (ii) छोटे ट्रॉलर 15 से 23 टन के हैं।

- (iii) हमें 2006 दरों में कोई समस्या नहीं थी। परन्तु, 2001 में दर में बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है। छोटे ट्रॉलरों से वर्तमान में 3,000/- प्रति केलेंडर माह वसूल किए जाते हैं। हम पिछले 2 वर्षों से परिचालन नहीं कर रहे हैं। कृपया पुरानी दर पर जाया जाए।
- (iv) ट्रॉलर नाव जितना स्थान (12 से 13 मीटर) ही घेरते हैं। ट्रॉलरों को नाव के बराबर माना जाए।
- (v) तूतीकोरिन तथा विजाग फिशिंग हारबर टीएमपी के न्यायाधिकार में आते हैं।
- (vi) फिशिंग नाव के लिए दरों की तुलना की जाए।
- (vii) हमें पत्तन द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। हम टैंकरों से पानी लेते हैं।

[वीपीटी अध्यक्ष: हम यह सेवा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं यदि प्रमारों का भुगतान किया जाता है।]

### वीपीटी

- (i) पत्तन को ड्रेजिंग करनी होती है, पानी उपलब्ध करवाना होता है, स्वच्छता और फिशिंग हारबर रूप में अन्य सुविधाएं देनी होती है जिसके लिए पत्तन व्यय करता है।
- (ii) हम याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर अपने विचार संप्रेषित कर देंगे।

14.1. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्रीज (एआईएफआई) वीपीटी को पृष्ठांकित प्रति के साथ अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा लिखित निवेदन किए थे। एआईएफआई के पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2018 की प्रति हमारे पत्र दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीपीटी को अग्रेषित की गई थी। इसका अनुस्मारक दिनांक 22 जून 2018 भेजा गया था। वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 26 जून 2018 द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी थीं। एआईएफआई द्वारा दिए गए लिखित निवेदनों और उनपर वीपीटी के प्रतिसाद का सार अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

14.2. वीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 26 जून 2018 द्वारा एआईएफआई द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा कही गई बातों पर अपनी टिप्पणियां भेजी थी। एआईएफआई द्वारा कही गई बातों और वीपीटी द्वारा दिए गए जवाब का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	एआईएफआई द्वारा कही गई बातें	वीपीटी द्वारा प्रेषित जवाब
(i)	हमारे सदस्यों की फिशिंग नावों के बर्थ किराया प्रमारों की वृद्धि के बिना, दिसम्बर 2000 के अनुसार यथास्थिति बनाये रखी जाए।	इस अवस्था में, अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि दरें 2006, 2011 और 2016 में संशोधित की गई थीं और टीएमपी द्वारा अनुमोदित किए गए थे और इन्हें लागू किया गया था।  इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना है कि एसोसिएशन के अनुरोध को संबोधित करने के लिए दरमान के संशोधन के समय पर जरूरी ध्यान रखा गया था, और वर्ष 2006 से आगे फिशिंग ट्रॉलरों/नावों के लिए निर्धारित न्यूनतम समेकित दरें निर्धारित की गई थीं।
(ii)	दोगुने और तिगुने प्रमारों को माफ किया जाए जो हमारे कुछ सदस्यों से वसूल किए गए थे।	प्रभार अनुमोदित तथा अधिसूचित दरमानों के अनुसार वसूल किए गए हैं, और इसलिए इस अवस्था में दोगुने और तिगुने प्रमारों को माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इन खंडों को 2006 से आगे के दरमानों के आगामी संशोधन में हटा दिए गए थे।
(iii)	हमारे कुछ सदस्यों से वसूल किए गए दंडात्मक ब्याज को माफ किया जाए।	प्रभार तत्समय मौजूदा दरमानों के अनुसार वसूल किए गए थे और अधिकांश फर्मों ने बिना किसी विवाद के प्रमारों का भुगतान किया था। अब 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद, एसोसिएशन (एआईएफआई) दंडात्मक ब्याज और दंडात्मक प्रमारों को माफ करने का अनुरोध कर रही है जोकि अब विचार के लिए औचित्यपरक नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि दरमानों में अब दंडात्मक प्रभार खंड मौजूद नहीं हैं क्योंकि इन्हें 2006 से लागू दरमानों के संशोधन के दौरान हटा दिया गया था।  वीपीटी ने बताया है कि रिट याचिका सं. 2003 की 9088, रिट याचिका सं. 2003 की 9585, रिट याचिका सं. 2003 की 20005 और रिट याचिका 2003 की 26404 में उच्च न्यायालय के संयुक्त आदेशों के अनुसरण में जरूरी उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं।
(iv)	हमारे कुछ सदस्यों से वसूल किए गए दंडात्मक प्रभार माफ किए जाएं।	

15.1. संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के अनुसार, हमारे पत्र दिनांक 8 मई 2018 द्वारा वीपीटी को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए स्मरण करवाया गया था और अपना प्रतिसाद शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया था क्योंकि इस मामले का हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश के मद्देनजर समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना है।

15.2. प्रतिसाद में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 17 मई 2018 द्वारा अपना प्रतिसाद भेजा था। वीपीटी ने सूचित किया था कि हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय, आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017, के अनुसार, वीपीटी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर आदेश पारित किए थे कि दरें टीएमपी द्वारा वर्ष 2006, 2011 और 2016 (अद्यतन) के दौरान पहले ही संशोधित की जा चुकी हैं और इसे वीपीटी द्वारा कार्यान्वित किया गया था। वीपीटी ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को संबोधित अपने पत्रों दिनांक 25 अप्रैल 2018 की एक-एक प्रति अग्रेषित की थी। उक्त पत्र में, वीपीटी ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट किया था कि पोत प्रमारों को कम करने का अनुरोध करने वाले

अभ्यावेदन की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि उक्त अभ्यावेदन के मुताबिक दरें वर्ष 2006, 2011 और 2016 के दौरान टीएमपी द्वारा पहले ही संशोधित की गई हैं। वीपीटी ने तदनुसार अभ्यावेदन को निपटान कर दिया गया मान लिया था।

16. चूंकि इस प्राधिकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निपटान करने के लिए इस प्राधिकरण हेतु निर्दिष्ट तारीख 18 जून 2018 को समाप्त हो चुकी है और उस समय एआईएफआई की टिप्पणियों पर वीपीटी के प्रतिवाद की प्रतीक्षा थी और मामले का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित समय और विस्तृत स्पष्ट आदेश पारित करने पर विचार करते हुए, श्री के. लक्ष्मण, भारत के सहायक महाधिवक्ता (एएसजीआई) से हमारे पत्र दिनांक 22 जून 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए अभ्यावेदन के निपटान के लिए हैदराबाद के माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय से 8 सप्ताह के समय विस्तार मांगने के लिए जरूरी कदम शीघ्र उठाये जाएं।

17.1. पूर्व अनुच्छेदों में उल्लिखित फिशिंग इंडस्ट्रीज के याचिकाकर्ताओं की अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निदेश से निकलने वाली एआईएफआई द्वारा कही गई उपर्युक्त बातों के अलावा, एआईएफआई ने वीपीटी को संबोधित और हमें पृष्ठांकित प्रति के साथ अपने पत्र दिनांक 2 मई 2018 द्वारा अपने सदस्यों के अभ्यावेदनों की एक-एक प्रति अग्रेषित की थी। वीपीटी को उनका अभ्यावेदन उनकी तत्संबंधी फिशिंग नावों के बर्थ किराया प्रमारों को क्लियर करने के लिए एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) पर विचार करने के लिए प्रस्ताव से संबंधित है।

17.2. प्रतिवाद में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 26 जून 2018 द्वारा इसपर अपनी टिप्पणियां भी भेजी थीं। वीपीटी ने बताया है कि ट्रॉलर स्वामियों ने बकाया देयताओं के एक मुश्त निपटान के लिए हाल ही में अनुरोध किया था क्योंकि फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी हालत में नहीं है, और इसकी वीपीटी द्वारा जांच की जा रही है।

18. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i) इस मामले में कार्यवाही रिट याचिकाओं सं. (क). भारत मरीन एक्सपोर्ट्स, सत्यसाई मरीन प्राइवेट लि. और श्री लक्ष्मी मरीन प्रोड्यूसर्स लि. द्वारा दाखिल 2003 की 9088, (ख). एस.बी.एस. मरीन एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि. और मै. कंचन गंगा सी फूड्स लि. की रिट याचिका सं. 2003 की 9585, (ग) श्री साई कृष्ण एग्रीकोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., मै. गोपाल कृष्ण इंटरप्राइजेज, मै. श्री गोपाल कृष्ण एसोसिएशन और डॉ. वाई.जी.के. मूर्ति द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2003 की 20005 और मै. गोवा ऑर कैरियर्स की रिट याचिका सं. 2003 की 26404 का निपटान करते हुए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायाधीश पी. केशव राव के संयुक्त आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के अनुपालन में की गई है। इनमें से दो याचिकाकर्ता अर्थात् भारत मरीन एक्सपोर्ट्स और सत्यसाई मरीन प्राइवेट लि. अपना केस पहले ही वापिस ले चुके हैं।

इस प्राधिकरण और वीपीटी को हैदराबाद में माननीय ज्यूडीकेचर उच्च न्यायालय का निदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा पोत प्रमारों को कम करने और ऐसे याचिकाकर्ताओं और अन्य जिन्होंने इस प्राधिकरण तथा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के समक्ष 08-12-2000 को हुई बैठक में स्वीकार किया था, से 16-05-2001 से पहले की मौजूदा पुरानी दरों जमा 15 प्रतिशत वृद्धि पर ही प्रभार जारी रखने की प्रार्थना करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों दिनांक 09-12-2000, 19-07-2001, 26-07-2001 और 19-08-2001 पर विचार करने और निपटान करने का निदेश है।

- (ii) यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए वीपीटी के उस समय के प्रस्ताव के आधार पर वीपीटी का इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पहला संशोधन था। उक्त आदेश आंध्र प्रदेश मेकेनाइज्ड फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (एपीएमएफबीओए) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फिशरी इंडस्ट्री (एआईएफआई), जिसने फिशिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व किया था, सहित प्रासंगिक पणधारियों के साथ यथोचित परामर्श प्रक्रिया तथा संयुक्त सुनवाई करने के बाद इस प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने फिशिंग पोतों के लिए लागू सभी प्रमारों पर 100 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की थी। उस समय प्रचलित प्रशुल्क पर गतिविधि वार निवल अधिशेष/घाटा दर्शाते सार विवरण ने (-) 239.28 प्रतिशत का निवल घाटा दर्शाया गया था जैसा कि उक्त आदेश के पैरा 21(vi) में में दिया गया है। फिशिंग गतिविधि के लिए अनुमोदित प्रशुल्क वृद्धि से संबंधित उक्त आदेश के प्रासंगिक पैरा 21(vi) उपर्युक्त पैरा 6.2 में दिया गया है और इसलिए दोहराया नहीं गया है। उक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने फिशिंग हारबर के लिए (तत्समय) मौजूदा दरों 100 प्रतिशत तक की वृद्धि अनुमोदित की थी हालांकि इसे सम्पूर्ण परिचालनात्मक व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया था। इस प्राधिकरण ने कहा था कि इस स्तर से अधिक कोई वृद्धि करने से उपयोगिताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा और इसलिए वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित 100 प्रतिशत तक वृद्धि को सीमित किया जाए। फिशिंग ट्रॉलरों (14 एनआरटी तक), फिशिंग ट्रॉलरों (14 एनआरटी से अधिक) और अभियांत्रिक फिशिंग नावों के लिए उस समय प्रचलित पृथक दर ढांचे के विपरीत, इस प्राधिकरण द्वारा, वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित, फिशिंग पोतों के लिए पोत संबंधित प्रमारों के लिए एकसमान दर अनुमोदित की थी।

- (iii) माननीय उच्च न्यायालय का संयुक्त आदेश यह रिकॉर्ड करता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने अभ्यावेदनों दिनांक 09-12-2000, 19-07-2001, 26-07-2001 और 19-08-2001 द्वारा इस प्राधिकरण तथा वीपीटी से अनुरोध किया था कि पोत प्रमारों को कम किया जाए और उन याचिकाकर्ताओं के लिए 16-05-2001 से पहले की मौजूदा पुरानी दरों जमा 15 प्रतिशत वृद्धि पर ही प्रभार जारी रखे जाएं जिन्होंने 08-12-2000 को हुई बैठक में स्वीकार किया था। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एआईएफआई जो फिशिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ने अपने पत्रों दिनांक 9 दिसम्बर 2010, 19 जुलाई 2001 और 26 जुलाई 2001 में फिशिंग इंडस्ट्री के लिए वीपीटी द्वारा प्रस्तावित 100 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर 15 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करने का अनुरोध किया था।

मई 2001 के उक्त आदेश के संदर्भ में, एआईएफआई ने अपने पत्र दिनांक 19 जुलाई 2001 और 26 जुलाई 2001 द्वारा पोत संबंधित प्रमारों को 100 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था और एपीएमएफबीओ ने अपने पत्र दिनांक 18 अगस्त 2001 द्वारा पुरानी दरों अर्थात् 16 मई 2001 से पहले की मौजूदा दरों को बनाये रखने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, वीपीटी ने अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद तब अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा इस प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया था कि फिशिंग पोतों के लिए निर्धारित एकसमान प्रशुल्क उचित



नहीं था। वीपीटी ने 16 मई 2001 से पहले प्रचलित फिशिंग पोतों के वर्गीकरण के अनुसार फिशिंग पोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरों के विभिन्न सैट बनाये रखने का प्रस्ताव किया था। वीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने वीपीटी के प्रस्ताव के अनुसार वीपीटी के पूर्व-संशोधित दरमानों में उपलब्ध फिशिंग पोतों के वर्गीकरण को बहाल करते हुए अगस्त 2001 का एक आदेश पारित किया था। फिशिंग पोत के लिए दरों में वृद्धि पूर्व संशोधित दर से 100 प्रतिशत पर बनाये रखी गई थी।

- (iv) पोत प्रभारों की वृद्धि के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों दिनांक 09-12-2000, 19-07-2001, 26-07-2001 और 19-08-2001 पर विचार करने के लिए माननीय न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में इस प्राधिकरण और वीपीटी को दिए गए निदेश के अनुपालन में, वीपीटी से एआईएफआई के अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई 2001, 26 जुलाई 2001 तथा वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2001 द्वारा अग्रप्रेषित एआईएफआई तथा एपीएमएफबीओए दोनों के अभ्यावेदन दिनांक 18 अगस्त 2001 पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही पत्तन (वीपीटी) से प्रतिसाद जो आखिरकार 26 जून 2018 को प्राप्त हुआ था, की प्राप्ति के बाद ही की जा सकी थी।

इस प्रकार, यह प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा निपटान करने की कार्यवाही शुरू करता है।

- (v). एआईएफआई द्वारा 2001 के अपने अभ्यावेदन में किया गया अनुरोध आदेश सं. टीएमपी/103/1999-वीपीटी दिनांक 16 मई 2001 में प्रदत्त 100 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर 15 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करने के लिए था। एपीएमएफबीओए ने फिशिंग गतिविधि के लिए 16 मई 2001 आदेश से पहले मौजूद दरों को जारी रखने का अनुरोध किया था। इस मामले की कार्यवाही के दौरान, एआईएफआई ने बर्थ किराया प्रभारों में दिसम्बर 2000 की दर में यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया था।

माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुपालन में, वीपीटी से ऊपर उल्लिखित अभ्यावेदनों पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी ने बताया है कि इस स्थिति में, अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि दरें 2006, 2011 और 2016 में संशोधित की गई थीं और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे वीपीटी द्वारा कार्यान्वित किया गया था। पत्तन ने निवेदन किया है कि एसोसिएशन के अनुरोध को संबोधित करने के लिए दरमानों के संशोधन के समय जरूरी ध्यान दिया गया था, और वर्ष 2006 से आगे फिशिंग ट्रॉलरों/बोटों के लिए न्यूनतम समेकित दरें निर्धारित की गई थीं। पत्तन ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा याचिकाकर्ताओं को भी सूचित किया था कि पोत प्रभारों को कम करने का अनुरोध करने वाले वर्ष 2000 और 2001 से संबंधित उनके अभ्यावेदन की जांच की गई थी और यह पाया गया है कि उक्त अभ्यावेदन के आधार पर दरें वर्ष 2006, 2011 और 2016 के दौरान इस प्राधिकरण द्वारा पहले ही संशोधित की जा चुकी हैं।

जैसाकि वीपीटी द्वारा बताया गया है, याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन के मद्देनजर, पत्तन ने बर्थ किराया, पाइलटेज तथा स्थानांतरण प्रभारों के मामले में फिशिंग पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभारों को कम करते हुए 2006 आदेश में सुधारात्मक कार्यवाई की थी। 2011 के प्रशुल्क आदेश में भी, इस गतिविधि के लिए कोई प्रशुल्क वृद्धि नहीं की गई थी और 2006 आदेश के स्तर पर यथास्थिति बनाये रखी गई थी।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और चूंकि वीपीटी ने कहा है कि अनुवर्ती संशोधन अर्थात् 2006 और 2011 के दौरान, वीपीटी उनके अभ्यावेदन के आधार पर पहले ही पोत संबंधित प्रभारों में कटौती कर चुका है जिसके बारे में पूर्व अनुच्छेदों में भी बताया गया है, यह प्राधिकरण इस मामले में वीपीटी द्वारा लिये गए निर्णय का समर्थन करता है और इन अभ्यावेदनों का तदनुसार निपटान करता है।

- (vi) (क) दुगुने और तिगुने प्रभारों से छूट, इसके कुछ सदस्यों पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज तथा दंडात्मक प्रभार छूट के लिए एआईएफआई द्वारा कही गई अन्य बातों के संबंध में, यह कहना है कि एआईएफआई द्वारा कही गई ये बातें माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, प्रभारों को छोड़ना संबद्ध पत्तन न्यास के अधिकार-क्षेत्र में आता है। इस संबंध में एआईएफआई द्वारा कही गई बातों पर अपनी टिप्पणियां पहले ही दे चुका है जिसके बारे में पूर्व अनुच्छेदों में बताया गया है। वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश फर्म उस समय प्रचलित एसओआर के अनुसार प्रभारों का पहले ही भुगतान कर चुके हैं और इसलिए 15 वर्षों से अधिक समय के बाद इन प्रभारों के दंडात्मक ब्याज को माफ करने का अनुरोध अब विचार करने के लिए औचित्यपरक नहीं है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि इन्हें 2006 के संशोधन के दौरान हटाया गया था और वीपीटी के मौजूदा एसओआर में मौजूद नहीं हैं।

- (ख) इस मामले की कार्यवाही के दौरान, एआईएफआई ने (i). यह कहते हुए कि ट्रॉलरों के लिए वर्गीकरण अब प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि वे फिशिंग नावों के रूप में पंजीकृत की गई हैं, और (ii). रु. 3000 प्रति माह की दर से जून 2016 में अनुमोदित मिनी ट्रॉलर के लिए मौजूदा दरें अर्थात् पत्तन देयताएं अधिक हैं, से संबंधित कुछ बातें कहीं थीं। एआईएफआई द्वारा उल्लिखित मामले संयुक्त न्यायनिर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में माननीय उच्च न्यायालय के निदेश से परे हैं।

- (ग) बर्थ किराया प्रभारों का भुगतान करने के लिए एकमुश्त निपटान पर विचार करने के लिए वीपीटी को एआईएफआई द्वारा दिए गए प्रस्ताव के संबंध में, यह कहना प्रासंगिक है कि माननीय उच्च न्यायालय का निदेश है कि पोत प्रभारों की वृद्धि के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदन दिनांक 9 दिसम्बर 2000, 19 जुलाई, 2001, 26 जुलाई 2001 और 19 अगस्त 2001 पर विचार किया जाए और उपयुक्त आदेश पारित किए जाएं। एआईएफआई द्वारा अपनी तत्संबंधी फिशिंग नावों के बर्थ किराया प्रभारों को चुकता करने के लिए एकमुश्त निपटान प्रस्तावों के बारे में अपने पत्र दिनांक 2 मई 2018 द्वारा कही गई बातें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्राधिकरण को निदेशित मामले से संबंधित नहीं हैं और इसलिए इस कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं। किसी मामले में पत्र

वीपीटी को संबोधित किया जाता है और वैसे इस प्राधिकरण से कोई मांग नहीं करता है। वीपीटी ने बताया है कि इस मामले की पत्तन द्वारा जांच की जा रही है।

19. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण इस मामले पर वीपीटी द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के संयुक्त आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों दिनांक 09-12-2000, 19-07-2001, 26-07-2001 और 18-08-2001 का निपटान करता है।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./194/18]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 10th August, 2018

**No. TAMP/22/2018-VPT.**— In compliance of the Common Order dated 20 December 2017 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh in the Writ Petition Nos.9088, 9585, 20005 and 26404 of 2003 and in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby considers and disposes of the the representations of the Petitioners as in the Order appended hereto.

### Tariff authority for major ports

Case No.TAMP/22/2018-VPT

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sree Lakshmi Marine Producers Ltd.,</li> <li>(ii) S.B.S. Marine Exports (P) Ltd.,</li> <li>(iii) M/s. Kanchana Ganga Sea Foods Ltd.,</li> <li>(iv) Shree Sai Krishna Agrocold Storage Pvt. Ltd.,</li> <li>(v) M/s. Gopala Krishna Enterprises,</li> <li>(vi) M/s. Sri Gopal Krishna Association,</li> <li>(vii) Dr. Y.G.K. Murthy and</li> <li>(viii) M/s. Goa Ore Carriers</li> </ul> | } | Petitioners |
|---|---|-------------|

### QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

### **ORDER**

(Passed on this 31<sup>st</sup> day of July 2018)

This case flows from the direction of Hon'ble Justice Shri P.Keshava Rao of the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh in the Common Judgment dated 20 December 2017 on the Writ Petition Nos.9088, 9585, 20005 and 26404 of 2003.

2. A letter dated 24 February 2018 was received on 19 March 2018 from Shri K.Lakshman, Assistant Solicitor General of India (ASGI), High Court of Judicature at Hyderabad with reference to the following Writ Petitions filed by various Petitioners against this Authority and others in the Hon'ble High Court:

- (i) Writ Petition No.9088 of 2003 filed by Bharath Marine Exports (Petitioner No.1), Satyasai Marine Private Ltd. (Petitioner No.2) and Sree Lakshmi Marine Producers Ltd. (Petitioner No.3) against Union of India, Ministry of Agriculture and Ministry of Surface Transport (Respondent Nos.1 and 2), TAMP (Respondent No.3), Visakhapatnam Port Trust [VPT] (Respondent No.4) and M/s.M.S.T.C. Limited (Respondent No.5).

*(W.P. so far as Petitioner No.1 viz. Bharath Marine Exports and Petitioner No.2 viz. Satyasai Marine Private Ltd. are concerned it has been dismissed as withdrawn as per Court Order dated 3 November 2008.)*

- (ii) Writ Petition No. 9585 of 2003 filed by S.B.S. Marine Exports (P) Ltd. (Petitioner No.1) and M/s. Kanchana Ganga Sea Foods Ltd. (Petitioner No.2) against Union of India (Respondent Nos.1 and 2), TAMP (Respondent No.3), VPT (Respondent No.4) and M/s.M.S.T.C. Limited (Respondent No.5).
- (iii) Writ Petition No. 20005 of 2003 filed by Shree Sai Krishna Agrocold Storage Pvt. Ltd. (Petitioner No.1), M/s.Gopala Krishna Enterprises (Petitioner No.2), M/s.Sri Gopal Krishna Association (Petitioner No.3) and Dr. Y.G.K. Murthy (Petitioner No.4) against Union of India (Respondent Nos.1 and 2), TAMP (Respondent No.3), VPT (Respondent No.4) and M/s.M.S.T.C. Limited (Respondent No.5).
- (iv) Writ Petition No.26404 of 2003 filed by M/s.Goa Ore Carriers against Union of India (Respondent Nos.1 and 2), TAMP (Respondent No.3) and VPT (Respondent Nos.4 and 5).

3.1. The ASGI in the said letter has informed that the above Writ Petitions came up for hearing before the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad on 20 December 2017 and after hearing the parties concerned, the Hon'ble Court has disposed of the Writ Petitions directing the Respondent Nos.3 and 4 to consider the aforesaid representations made by the Petitioners relating to the enhancement of the vessel charges and pass appropriate order within a period three months from the date of receipt of copy of the order.

3.2. The ASGI has, along with his said letter, forwarded an original certified copy of the Hon'ble High Court Common Order dated 20 December 2017 of the Hon'ble Sri Justice P. Keshava Rao in the above petitions. The operative part of the Order is reproduced below:

- “6. *A perusal of averments --- petitioners. Be that as it may, it is placed on record that the Petitioners have submitted representations, dated 09.12.2000, 19.07.2001, 26.07.2001 and 19.8.2001 to the Director, Tariff Authority for Major Port Trusts, New Delhi as well as the Chairman, Visakhapatnam Port Trust i.e. respondents 3 and 4 requesting to reduce the vessel charges and continue to charge only the old rates existing prior to 16.05.2001 plus 15% increase which petitioners and others have accepted in the meeting held on 08.12.2000. Therefore, the learned counsel representing the petitioners requested the Court to direct the respondents 3 and 4 to consider the said representations and pass appropriate orders.*
- 7. *Keeping in view the submissions made by the learned counsel for the petitioners and also the averments made in the counter-affidavit, this Court feels appropriate to direct the respondents 3 and 4 to consider the aforesaid representations made by the petitioners relating to the enhancement of the vessel charges and pass appropriate orders within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order.*
- 8. *With the above directions, all the four writ petitions are disposed of. There shall be no order as to costs.*
- 9. *The miscellaneous petitions, if any, pending in these writ petitions shall stand closed.”*

3.3. Thus, in short, the Hon'ble Single Judge has directed the Respondent No.3 (TAMP) and Respondent No.4 (VPT) to consider the representations dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and 19 August 2001 made by the petitioners relating to the enhancement of the vessel charges and pass appropriate orders within a period of three months from the date of receipt of a copy of the order.

3.4. The Order of the Hon'ble Single Judge was received by the office on 19 March 2018. Hence, 3 months from that date expires 18 June 2018 by which the Order is to be passed by this Authority.

4. Before proceeding to examine the representations made by petitioners and Association of Indian Fishery Industry (AIFI), it may be relevant to bring out the brief history of the matter. With reference to the Writ Petition No.9088 of 2003 and Writ Petition No.9585 of 2003, the following brief history of the case is given below:

- (i) This Authority has passed an Order No.TAMP/103/99-VPT dated 16 May 2001 approving the general revision of the VPT Scale of Rates. In the said Order, this Authority approved a 100% tariff increase on all the charges applicable for fishing vessels. This decision was taken based on the cost statement of the fishing vessel which depicted a deficit of 239% for the years 2000-01 and 2001-02. The tariff hike was, however, restricted only to 100% to atleast to cover the operating expenditure incurred by the VPT. A uniform rate for fishing vessels was approved based on grouping as proposed by the VPT (Para 21 (vi) & (viii) of the Order).
- (ii) Subsequently, the VPT based on the representations of Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boat Operators Association (APMFBOA) and Association of Indian Fishery Industry (AIFI) requested this Authority to reinstate the earlier categorisation of the fishing vessels since it admitted that clubbing of different categories of fishing vessel caused undue burden on the mechanised boats and fishing vessels of lower NRT. Accordingly, this Authority passed another Order on 30 August 2001 reinstating the earlier categorisation of

the fishing vessels. However, the rates were increased by 100% over the pre-revised rate since this Authority did not find any justification for reviewing the percentage of upward revision of tariff decided earlier for fishing vessels.

- (iii) Bharath Marine Exports had filed a Writ Petition No. 9088 of 2003 in the High Court of Andhra Pradesh against TAMP, the VPT and the others. M/s.SBS Marine Exports (P) Limited and M/s.Kanchan Ganga Sea Foods Limited have also filed a similar Writ Petition No.9585 of 2003 in the High Court of Andhra Pradesh challenging the Orders passed by Authority.

5.1. On perusing the Writ Petition No.20005 of 2003 and 26404 of 2003 it is seen that the Hon'ble Court while passing common Order disposing of the said Writ Petitions viz., 9088, 9585, 20005 and 26404 of 2003, has directed this Authority and VPT to consider the representations dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and 19 August 2001 made by the petitioners relating to the enhancement of the vessel charges and pass appropriate orders within a period of three months from the date of receipt of a copy of the order.

5.2. As regards, representations dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and 19 August 2001 stated to have been made by the petitioners to TAMP and to VPT relating to the enhancement of the vessel in the Order of the Hon'ble Single Judge, it is to state that we have not received representation dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and 19 August 2001 from the Petitioners directly. Such representations are not included as part of the W.P. Nos.9585 and 9008 of 2003 either. However, on referring to the general revision file of the VPT pertaining to that period, it is seen that the Association of Indian Fishery Industries (AIFI) which represents the fishing industry has filed representation dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and representation dated 18 August 2001 [it is not 19.08.2001] from the Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boat Operators Association (APMFBOA) which was forwarded by VPT vide its letter dated 25 August 2001.

**A. Representation of Association of Indian Fishery Industries (AIFI) dated 9 December 2000 and relevant portion of TAMP Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 16 May 2001**

6.1. The representation dated 9 December 2000 received from the Association of Indian Fishery Industries [AIFI] is addressed to TAMP. The main points of the said representation are as under:

- (i) AIFI had attended the meeting held on 8 December 2000 (Joint Hearing) at VPT, Visakhapatnam. As per the discussions on that day, AIFI submitted that they are willing to take over the Management of Fishing Harbour Slipway Complex as per the Chairman's proposals.
- (ii) The proposal of VPT to increase the charges of Slipway Complex and Dry-dock in Fishing Harbour by 100% is not reasonable and AIFI has requested to increase these charges on par with the other charges of VPT which were proposed to be increased by 15%.

6.2. As regards, the AIFI's representation dated 9 December 2000 brought out in para 6.1 above, it is relevant to state that the said representation was considered by this Authority in its Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 16 May 2001 at para 21(viii), in the general revision of SOR of VPT. The relevant para of the said Order is reproduced below:

*“(viii) In case of iron ore handling activity and fish harbour, the Port will continue to incur operational losses, even after the revised rates proposed by the Port are implemented. The Port has never got remunerative rates for handling iron ore ever since the inception of outer harbour. According to the VPT, though the inner harbour was capable of handling iron ore exports, the outer harbour facility was created to handle larger vessels to make export competitive. For various considerations, the Port was not allowed in the past to increase the rates based on its cost. Further, the anticipated traffic also did not materialise. The deficit position emerging now is, therefore, mainly due to accumulation of (appropriate) actions (not) taken in the past. Tariff reforms cannot be made at one go. Besides, in this case, the VPT is also apprehensive of traffic diversion, if rates go up steeply, which will only aggravate the problem for the Port. That being so, the increase in rates to the level proposed by the Port is approved, leaving the uncovered operational expenditure under this activity to be met out of surplus from other activities. Likewise, the existing rates for fish harbour will also increase by 100% even though it may not be sufficient to meet entire operational expenditure. Since any increase beyond this level will put an undue burden on users, the increase has been limited to 100%. Here again, the operational loss is to be met out of surplus from other activities. The offer made by Association of Indian Fishery Industries (AIFI) to take over the management of fishing harbour is totally out of context. The Scale of Rates being revised now is with reference to the cost incurred by the VPT. If there is any change in management (other than the VPT), it is needless to mention that the tariffs for fishing harbour will stand deleted from the Scale of Rates of the VPT. Anyway, the issue of change in management is not an issue to be considered by this Authority. The AIFI may move the appropriate forum with its proposal for taking over the fishing harbour.”*

**B. Representation of Association of Indian Fishery Industries (AIFI) dated 19 July 2001 and 26 July 2001.**

7. The representation dated 19 July 2001 received from the AIFI addressed to TAMP with a copy endorsed to Ministry of Agriculture was received after the Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 16 May 2001 was passed by this Authority and notified in the Gazette of India on 4 June 2001. The representation dated 26 July 2001 received from the AIFI was addressed to VPT with a copy endorsed to TAMP referring to AIFI letter dated 19 July 2001 and requesting this Authority to amend the Order dated 16 May 2001 while reducing the rates from 100% to 15% with immediate effect. The submissions made in both the representations are similar. The main points made by AIFI in the above said letters are as summarised below:

- (i) Referring to the Joint hearing held on 8 December 2000 at VPT (on the general revision of SOR of VPT) and AIFI letter dated 9 December 2001, the AIFI has stated they are surprised and shocked to receive information regarding 100% hike in slip way complex and dry dock rates in the Order passed by this Authority on 16 May 2001 and notified in Gazette of India dated 4 June 2001 vide Gazette No.143.
- (ii) It is not fair in taking unilateral decision to increase the port charges abnormally by 100% at a time in spite of request during the meeting that was held on 8 December 2000. AIFI regrets for this unilateral decision which will definitely hamper the Fishing Industry which is earning valuable foreign exchange to our Nation.
- (iii) Visakhapatnam Fishing Harbour is the only Harbour developed in India for working of deep sea fishing vessels. This Harbour was created with the Ministry of Agriculture, Government of India funds and management of Fishing Harbour has been entrusted to VPT.
- (iv) The general hike of Port Charges is only 10 to 15% for majority of the services whereas Fishing Harbour service charges has been hiked by 100% without considering AIFI plea on 8 December 2000 at the meeting to increase upto 15%.
- (v) The Indian Deep Sea Fishing Industry is passing through very difficult situations due to hiked diesel oil, spare parts and maintenance charges. The Industry strength has come down from 160 to 90 vessels. The balance 70 vessels has been scraped for non-viability of operations. The Fishing Harbour is a National asset and in fact AIFI have written letters for handing over the Fishing Harbour management including slip way and dry dock to the AIFI, the only body representing Indian Deep Sea Fishing Industry. Hence, the AIFI requests not to club fishing harbour services with the Port services and Visakhapatnam Fishing Harbour as it is the National asset created by Ministry of Agriculture.
- (vi) The VPT has been entrusted for the maintenance of the fishing harbour. The representation made by the VPT regarding expenses and showing 239% loss is not acceptable to the Fishing Industry. Please hand it over to the AIFI for the Management of fishing harbour and AIFI will make it a profitable one based on the rates before 16 May 2001 rates. In the meanwhile, AIFI has requested to charge only the old rates existing prior to 16 May 2001 and keep in abeyance the increased rates till the Visakhapatnam fishing harbour handing over matter is settled.

**C. Representation of Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boat Operators' Association (APMFBOA) dated 18.08.2001 (The Member of Parliament letter dated 19.08.2001):**

8.1. As regards representation dated 19 August 2001 referred in the Judgement, it is to state that the VPT has vide its letter dated 25 August 2001 has stated that various association connected to fishing Industry have submitted representation dated 19 August 2001 through Member of Parliament (MP) (Lok Sabha) requesting to reconsider the tariff fixed for fishing vessels. The VPT under cover of its said letter has forwarded a copy of the representation dated 18 August 2001 of Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boat Operators' Association (APMFBOA) addressed to MP, a copy of representation dated 8 August 2001 of Deep Sea Trawlers Owners Welfare Association (DSTOWA) addressed to VPT, and representation of AIFI dated 18 August 2001 to VPT.

8.2. The main points made in the representation of APMFBOA in its letter dated 18 August 2001 are summarised below:

- (i) We are paying berth charges ₹229.30 ps. per month per boat, whereas recently the Visakhapatnam Port authority has increased rates abnormally, berth charges on Mechanised Fishing Boats which is highly impossible for paying such high rates. The particulars are given below:

Item	Old Rates	New Rates
Wharfage	₹53.80	₹1,075.00
Port Dues	Nil	143.50 Newly introduced
Berth Charges	5.50 up to 20 tons per day	9.90 up to 10 tons

Berth Charges to be calculated on Net tonnage basis only.		14.85 up to 15 tons
		17.82 up to 18 tons
		18.81 up to 19 tons
Water charge	₹5.00	81.40 per 1000 lr.
Levy on Diesel	0.04	0.08 + ₹10/- K.L.

- (ii) On old rates we are paying per month ₹229.30. On new rates we have to pay per month ₹2,069.00. At present the Fishing industry is in very sick position due to increased diesel Oil rates and other items. Whereas the Prawn rates are decreased very high. Because of the above situation maximum boat owners are not operating their fishing boats.
- (iii) In view of the above, it is our humble request kindly consider our most genuine problem and kindly continue the old rates for helping poor fishermen boat owners.

9.1. The representation dated 26 July 2001 was forwarded to VPT vide our letter dated 9 August 2001 requesting VPT to examine and furnish its comments.

9.2. In response, the VPT vide its letter dated 25 August 2001 and after taking consideration the representation dated 18 August 2001 of AMFBOA forwarded by the Member of Parliament had furnished the following comments:

- (i) In consonance with the policy of dispensing with cross- subsidisation, the port had taken a view to hike the charges for the fishing vessels by 100% to bridge the deficit of 239% reflected by the cost statement for the cost centre 'Fish Harbour'; and, also to arrest the flow of subsidy from commercial vessels to fishing vessels.
- (ii) The port purchases water from the Municipal Corporation at industrial rates and supplying the same to the fishing vessels after adding 2% as incidentals; and, hence, the water charges were also hiked. The fishery industry was not comfortable with the rates for water supply. The VPT has, therefore, decided to stop supply of water and requested the fishing vessels to purchase water from private operators.
- (iii) The mechanised boats, mini trawlers and big trawlers were grouped under one category while proposing the rates.
- (iv) The various associations connected to fishing industry viz., Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boat Operators Association, Deep Sea Trawler Owner's Association and Association of Indian Fishery Industry have submitted representation on 19 August 2001 through Member of Parliament (LS) requesting to reconsider the tariff fixed for fishing vessels. Copies of these representations are furnished by the VPT.
- (v) After careful examination of issues involved, the VPT felt that grouping of fishing boats having limited endurance and low cost with trawlers having high endurance and high cost is not at all logical. Further, the frequency of calls of mechanised boats is much more compared to the trawlers, which justifies having a relatively lower rate for mechanised boats. The VPT, therefore, felt appropriate to adopt different sets of rates for the different categories of vessels detailed below:
  - (a) Mechanised boats
  - (b) Mini fishing trawlers upto 14NRT (upto 22 GRT)
  - (c) Fishing Trawlers over 14 NRT (over 22 GRT).
- (vi) In view of the severe crisis being faced by the fishery industry and due to un-remunerative prices in the international market, the VPT had also requested this Authority to take a sympathetic view and re-fix the tariffs for the mechanised boats.

9.3. Based on the VPT letter dated 25 August 2001, this Authority has passed an Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 30 August 2001 reviewing the tariff approved for fishing vessels in the Order dated 16 May 2001. In the said Order of August 2001, this Authority has reinstated the earlier categorisation of the fishing vessels. The increase in rates was, however, maintained at 100% over the pre-revised rate. The relevant para 6(ii) of the Order dated 30 August 2001 is reproduced below:

*Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boats Operator's Association and the Association of Indian Fishery Industries (AIFI) have sent representations against the Port charges prescribed in the revised Scale of Rates for fishing boats. While considering their representation, it is observed that in the pre-revised Scale of Rates of the VPT, rates for fishing vessels were prescribed by grouping them into three categories viz., (a) mechanised fishing boats; (b) fishing trawlers (upto 14 NRT); and, (c) fishing trawlers (above 14 NRT). The VPT did not, however, propose to maintain this categorisation in its proposed Scale of Rates. In the general revision case the VPT had proposed a uniform tariff for all the categories of fishing vessels considering 100% hike on the*

*pre-revised tariffs on fishing trawlers. As a result of this, the mechanised fishing boats have been unduly burdened with the tariff hikes applicable to fishing trawlers.*

*It is to be admitted that the clubbing of different categories of fishing vessels made for tariff purposes is an error, which missed an indepth scrutiny by this Authority while dealing with the general revision proposal. This had happened since the attention was engaged in other tariff items which were significant from the point of view of Port's revenue. Further, the representatives of the fishery industry who participated in the joint hearings had only argued against a 100% hike in tariffs; but, never brought out clearly the implications of clubbing of different categories of fishing vessels proposed by the VPT.*

*The VPT has also now indicated that clubbing of all the categories of fishing vessels for proposing the tariff is illogical. The VPT has also requested to maintain different sets of rates for different categories of fishing vessels. The categorisation now proposed by the VPT is the same as that was available in its pre-revised Scale of Rates.*

*This Authority finds that it will be logical and reasonable to reinstate the categorisation of fishing vessels that was available in the pre-revised Scale of Rates of the VPT. With the reinstatement of the categorisation of fishing vessels available earlier, the respective pre-revised rates are also to be revised by 100% for the reasons given in sub-para (i) above."*

9.4. Thus, as per our records, the representations referred by the Hon'ble High Court were considered at the time of passing the relevant tariff Orders.

10. In the Order of Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and for the State of Andhra Pradesh with reference to the Writ Petition Nos.9088, 9585, 20005 and 26404 of 2003 filed by various Petitioners, the Hon'ble High Court has ordered TAMP and VPT to consider the representations dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and 19 August 2001 made by the petitioners relating to the enhancement of the vessel charges and pass appropriate orders within a period of three months from the date of receipt of a copy of the order.

11.1. In compliance of the Order of the Single Bench Judge, the representation of the AIFI dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and representation of the AIFI and APMFBOA both dated 18 August 2001 forwarded by the VPT vide its letter dated 25 August 2001 was taken up as a separate tariff case. This was intimated to the Petitioners vide our letters dated 3 April 2018 and 9 April 2018 in compliance with the direction of the Hon'ble High Court and was also intimated to users associations viz. AIFI, APMFBOA and DSTOWA, whose representations were referred in the Judgement.

11.2. To summarise, the main points of the AIFI and APMFBOA in their representation are as follows:

- (i) AIFI has requested for 15% increase as against 100% increase granted in Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 16 May 2001.
- (ii) APMFBOA has requested to continue with the rates existing prior to 16 May 2001 Order for fishing activity.

12.1. As per the direction of Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad, the VPT is also to consider the representations made by the Petitioners. Hence, a copy of each of the representations of the AIFI dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and representation of the AIFI and APMFBOA both dated 18 August 2001 forwarded by the VPT vide its letter dated 25 August 2001 was forwarded to VPT vide our letter dated 3 April 2018 with a request to furnish its response by 10 April 2018.

12.2. The VPT vide its letter dated 3 April 2018 has stated that the rates for the fishing trawlers were revised in the year 2006, 2011 and 2016 being the latest rates of VPT SOR after filing of the petition.

12.3. Subsequently, the VPT vide its letter dated 17 May 2018 has furnished further response, which is brought out at subsequent paragraph.

12.4. Simultaneously, the petitioners as well as Association of Indian Fishery Industries (AIFI) and Deep Sea Trawler Owners Welfare Association were also intimated that in compliance of said the Common Order dated 20 December 2017 of the Hon'ble Sri Justice P. Keshava Rao of Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad in the above petitions, the representations made by AIFI dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and representation dated 18 August 2001 of AIFI and APMFBOA forwarded by VPT vide its letter dated 25 August 2001 to TAMP are again taken up for consideration and being forwarded to VPT for its comments.

12.5. The letters sent to Petitioners viz. M/s.Goa Ore Carriers, M/s. Sree Lakshmi Marine Producers Ltd. (SLMPL), M/s.Kanchana Ganga Sea Foods Ltd. and S.B.S. Marine Exports (P) Ltd. dated 3 April 2018 and 9 April 2018 were returned back by postal department on the ground of 'Insufficient address', 'No such Address in this door no.' 'Closed' and 'Left'. Hence, VPT vide our letters dated 19 April 2018, 23 April 2018, and 27 April 2018 was requested to intimate the correct address. The letters were again re-sent to the petitioner on the address communicated by VPT.

However, since the letter addressed to petitioners were again returned back by the postal department, the letter dated 16 May 2018 was addressed to Advocate of the Petitioners i.e. Shri V.S.R. Anjaneyulu requesting to kindly arrange to deliver the undelivered letters to the four Petitioners viz. M/s. Sree Lakshmi Marine Products Ltd., M/s. Goa Ore Carriers, M/s. Kanchana Ganga Sea Foods Ltd. and S.B.S. Marine Exports (P) Ltd and to forward the correct addresses alongwith the e-mail id, telephone number and fax number of the above said Petitioners so as to enable to communicate with them hence forth. Simultaneously, VPT vide our letter dated 16 May 2018 was again requested to intimate correct addresses of the Petitioners and deliver the undelivered letters to the Petitioners and also obtain their acknowledgment since this case flows from the direction of the Hon'ble High Court. Further, the VPT was also requested to forward the correct addresses alongwith the email id, telephone number and fax number of the above said Petitioners so as to enable to communicate with them hence forth.

12.6. In this regard, VPT vide its letter dated 17 May 2018 has intimated that some of the firms letters are not delivered despite sending registered post and the same was informed during joint hearing.

13. A joint hearing in this case was held on 25 April 2018 at the VPT premises. At the joint hearing, the VPT and Petitioners have made the following submissions:

**Privans Fisheries and Member of Association of Indian Fishery Industries [AIFI]**

- (i) Earlier, the classification was for trawlers which are not relevant now we are registered as fishing boats.
- (ii) Mini Trawler are 15 to 23 Tons.
- (iii) We have no problem in 2006 rates. But, in 2001 the rate has been increased exorbitant. The mini trawlers are presently charged 3,000/- per calendar month. We are not operating for last 2 years. Please go back to old rate.
- (iv) Trawlers occupy space as much as boat (12 to 13 mtrs.). Treat trawlers at par with boat.
- (v) Tuticorin and Vizag fishing harbor come under TAMP jurisdiction.
- (vi) A comparison of rates for fishing boat may be done.
- (vii) We are not supplied water by the port. We get water by tankers.  
[VPT Chairman: We are ready to provide service if charges are paid.]

**VPT**

- (i) Port has to do dredging, provide water, sanitation and other facilities as fishing harbor for which port incurs expenditure.
- (ii) We will convey our views on the representation of Petitioners.

14.1. The Association of Indian Fishery Industries (AIFI) vide its letter dated 25 April 2018 with a copy endorsed to VPT has made written submissions. A copy of the letter dated 25 April 2018 of AIFI was forwarded to VPT as feedback information vide our letter dated 14 May 2018. This was followed by reminder dated 22 June 2018. The VPT furnished its comments vide its letter dated 26 June 2018. A summary of the written submissions made by AIFI and response of VPT thereon is brought out in subsequent paragraphs.

14.2. The VPT vide its e-mail dated 26 June 2018 has furnished its comments on the points made by the AIFI vide its letter dated 25 April 2018. A summary of the points made by AIFI and reply furnished by VPT is tabulated below:

Sl. No.	Points made by AIFI	Reply furnished by VPT
(i)	To maintain Status co as on December 2000, without enhancement of the Berth Hire charges of the Fishing boats of our members.	At this stage, the request cannot be considered as the Rates were revised in 2006, 2011 and 2016 and were approved by the TAMP and the same were implemented.  Further, it is also to mention that due care was taken at the time of revision of Scale of Rates to address the request of the Association, and nominal consolidated rates were fixed for fishing trawlers/ boats from year, 2006 onwards.
(ii)	To waive the Doubling and Tripling charges that	Charges are levied accordingly as per approved and



	were levied on some of our members.	notified Scale of Rates, and hence the waiver of doubling and tripling charges at this stage does not arise, as those clauses were removed in ensuing revision of Scale of Rates from 2006 onwards.
(iii)	To waive the Penal interest levied on some of our members.	The charges were levied as per the then existing Scale of Rates and most of the firm have paid the charges without any dispute. Now after lapse of more than 15 years, the Association (AIFI) is requesting for waiver of penal interest and penal charges which may not be justifiable for consideration now. However, it is to mention that no more penal charges clause exist in the Scale of Rates as the same were removed during revision of Scale of Rates w.e.f. 2006.  The VPT has stated that in pursuance of the High Court Common Orders in W.P. No. 9088 of 2003, W.P.No. 9585 of 2003, W.P.No. 20005 of 2003 and W.P. No.26404 of 2003 necessary appropriate orders may be passed.
(iv)	To waive the Penal charges levied on some of our members.	

15.1. As agreed at the joint hearing, the VPT vide our letter dated 8 May 2018 was reminded to consider the representations of Petitioners and was requested to expedite its response as the case has to be disposed of in a time bound manner in view of the direction from the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad.

15.2. In response, the VPT vide its letter dated 17 May 2018 has furnished its response. The VPT has informed that as per the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad, Orders dated 20 December 2017, VPT has passed Orders on the representations of petitioners that the rates have been already revised by TAMP during the year 2006, 2011 and 2016 (latest) and the same was implemented by VPT. The VPT has forwarded a copy each of its letters dated 25 April 2018 addressed to the Petitioners in this regard. In the said letter the VPT has clarified to the petitioner that the representation requesting to reduce the vessel charges was examined and is found that pursuant to the said representation the rates have been already revised by TAMP during the year 2006, 2011 and 2016. The VPT has treated the representation as disposed accordingly.

16. Since the cut off date for this Authority to dispose of the representation of petitioners ended on 18 June 2018 and the response of VPT was awaited on the comments of AIFI at that point of time and considering the time required to analyse the case and pass a detailed Speaking Order, Shri K.Lakshman, Assistant Solicitor General of India (ASGI) was requested vide our letter dated 22 June 2018 to take necessary steps early to seek extension of time of 8 weeks from the Hon'ble High Court of Judicature of Hyderabad to dispose of the representation filed by Petitioners.

17.1. Apart from the above points made by AIFI flowing from the direction of the Hon'ble High Court to consider the representation of Petitioners of Fishing Industries stated in earlier paragraphs, the AIFI vide its letters dated 2 May 2018 addressed to VPT with a copy endorsed to us has forwarded copy each of the representations of their members. Their representation to VPT relates to proposal to consider the One Time Settlement (O.T.S.) for clearing the berth hire charges of their respective Fishing boats.

17.2. In response, the VPT has also vide its letter dated 26 June 2018 furnished its comments thereon. The VPT has stated that Trawler Owners have requested recently for one time settlement of outstanding dues as the Fishing industry is not in good shape, and the same is under examination by VPT.

18. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) This case is processed in compliance of the Common Order dated 20 December 2017 of the Hon'ble Sri Justice P.Keshava Rao of Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and for the State of Andhra Pradesh disposing of the Writ Petitions No. (a). 9088 of 2003 filed by Bharath Marine Exports, Satyasai Marine Private Ltd. and Sree Lakshmi Marine Producers Ltd., (b). W.P. No.9585 of 2003 S.B.S. Marine Exports (P) Ltd. and M/s. Kanchana Ganga Sea Foods Ltd., (c). W.P. No.20005 of 2003 filed by Shree Sai Krishna Agrocold Storage Pvt. Ltd., M/s.Gopala Krishna Enterprises, M/s.Sri Gopal Krishna Association and Dr. Y.G.K. Murthy and (d). W.P. No.26404 of 2003 M/s.Goa Ore Carriers. Of these two Petitioners viz. Bharath Marine Exports and Petitioner and Satyasai Marine Private Ltd. have already withdrawn their case.

The direction of the Hon'ble High Court of Judicature at Hyderabad to this Authority and the VPT is to consider and dispose of representations dated 09.12.2000, 19.07.2001, 26.07.2001 and 19.8.2001 made by the Petitioners praying to reduce the vessel charges and continue to charge only the old rates existing prior to 16.05.2001 plus 15% increase which petitioners and others have accepted in the meeting held on 08.12.2000 before this Authority and Visakhapatnam Port Trust (VPT).

- (ii) It is relevant here to state that the tariff Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 16 May 2001 was the first revision approved by this Authority of VPT based on the then proposal of the VPT for general revision of the SOR. The said Order was passed by this Authority after following due consultation process and joint hearing with relevant stakeholders including the Andhra Pradesh Mechanised Fishing Boat Operators Association (APMFBOA) and Association of Indian Fishery Industry (AIFI) who represented the Fishing Industry. In the said Order, this Authority has approved a 100% tariff increase on all the charges applicable for fishing vessels. The summary statement showing activity wise net surplus/ deficit at the then prevailing tariff reflected net deficit of (-) 239.28% as brought out in para 21(vi) of the said Order. Relevant para 21 (viii) of the said Order relating to tariff increase approved for fishing activity is brought out in para 6.2. above and hence not reiterated. In the said Order, this Authority had approved increase by 100% over the (then) existing rates for fishing harbour even though it was not found sufficient to meet entire operational expenditure. This Authority held that any increase beyond this level will put an undue burden on users and hence limited the increase to 100% as proposed by the VPT. As against separate rate structure then prevailing for Fishing Trawlers (Upto 14 NRT), Fishing Trawlers (above 14 NRT) and mechanised fishing boats, a uniform rate for vessel related charges for fishing vessels was approved by this Authority as proposed by the VPT.
- (iii) The Common Order of the Hon'ble High Court records that Petitioners had vide their representation dated 09.12.2000, 19.07.2001, 26.07.2001 and 19.8.2001 requested this Authority and VPT to reduce the vessel charges and continue to charge only the old rates existing prior to 16.05.2001 plus 15% increase which petitioners and others have accepted in the meeting held on 08.12.2000. In this regard, it is clarified that the AIFI which is representing the Fishing Industry has in their letters dated 9 December 2010, 19 July 2001 and 26 July 2001 requested to consider 15% increase as against 100% increase proposed by the VPT for fishing activity.

With reference to the said Order of May 2001, AIFI vide its letter dated 19 July 2001 and 26 July 2001 had requested to reduce the vessel related charges from 100% increase to 15% increase and the APMFBOA vide its letter dated 18 August 2001 had requested to keep the old rates i.e. rates existing prior to 16 May 2001. In this regard, the VPT after examining the representations had pointed out to this Authority vide its letter dated 25 August 2001 then that uniform tariff prescribed for fishing vessels was not appropriate. The VPT proposed to retain different sets of rates for the different categories of fishing vessels as per the categorization of fishing vessels prevailing prior to 16 May 2001. Based on the request made by the VPT, this Authority passed an Order of August 2001 reinstating the categorisation of fishing vessels that was available in the pre-revised Scale of Rates of the VPT as proposed by VPT. The increase in rates for fishing vessel was maintained at 100% over the pre revised rate.

- (iv) In compliance with the direction of the Hon'ble Justice in the Order dated 20 December 2017 to this Authority and to VPT to consider the representation of Petitioners dated 09.12.2000, 19.07.2001, 26.07.2001 and 19.08.2001 relating to the enhancement of the vessel charges, the VPT was requested to consider the representation of the AIFI dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and representation of the AIFI and APMFBOA both dated 18 August 2001 forwarded by the VPT vide its letter dated 25 August 2001.

This case could be processed by this Authority for finalisation only after receipt of response from the port (VPT) which was last received on 26 June 2018

This Authority thus proceeds to consider and dispose of the representations of Petitioners as directed by the Hon'ble High Court.

- (v) The request made by AIFI in its representations of 2001 was to consider 15% increase as against 100% increase granted in Order No.TAMP/103/1999-VPT dated 16 May 2001. APMFBOA has requested to continue with the rates existing prior to 16 May 2001 Order for fishing activity. During the processing of this case, the AIFI has requested to maintain status quo in rate as of December 2000 in the berth hire charges.

In compliance with the direction of the Hon'ble High Court, the VPT was requested to consider the above referred representations. The VPT has stated that at this stage, the request cannot be considered as the rates were revised in 2006, 2011 and 2016 and were approved by this Authority and the same were implemented by the VPT. The port has submitted that due care was taken at the time of revision of Scale of Rates to address the request of the Association, and nominal consolidated rates were fixed for fishing trawlers/ boats from year 2006 onwards. The port has also intimated to the Petitioners vide its letter dated 25 April 2018 that their representation pertaining to the years 2000 and 2001 requesting to reduce the vessel charges was examined and it is found that pursuant to the said representation the rates have been already revised by this Authority during the years 2006, 2011 and 2016.

As, stated by the VPT, in view of the representation of the Petitioners the port has taken corrective action in the 2006 Order by reducing the vessel related charges for fishing vessels in respect of berth hire, pilotage and shifting charges. In the tariff Order of 2011 as well, there was no tariff increase for this activity and status quo was maintained at the level of 2006 Order.

In view of the above position and since the VPT has stated that during the subsequent revision i.e. 2006 and 2011, the VPT has already based on their representation reduced the vessel related charges which is also brought out in the earlier paragraphs, this Authority endorses the decision taken by the VPT in this matter and disposes of these representations accordingly.

- (vi) (a) As regards the other points made by the AIFI to waive the doubling and tripling charges, waive the Penal interest and penal charges levied on some of its members, it is to state that these points made by AIFI are beyond the scope of the direction of the Hon'ble High Court. Further, waiver of charges falls under the domain of the concerned Port Trust. The VPT has already given its comments on the points made by the AIFI in this regard which has been brought out in the earlier paragraphs. The VPT has clarified that most of the firms have already paid the charges as per then prevailing SOR and hence request for waiver of penal interest of these charges after lapse of more than 15 years is not justifiable for consideration now. The port has clarified that these were removed during revision of 2006 and do not prevail in existing SOR of VPT.
- (b) During the processing of this case, the AIFI has made a few points relating to (i). Classification for trawlers stating that they are not relevant now as they are registered as fishing boats, and (ii). current rates i.e. Port dues for mini trawler approved in June 2016 at `3000 per month is at higher side. These matters referred by AIFI are beyond the direction of the Hon'ble High Court in the common Judgment dated 20 December 2017.
- (c) As regards the proposal of AIFI to the VPT to consider one time settlement for clearing berth hire charges, it is relevant to state that the direction of the Hon'ble High Court is to consider the representation dated 9 December 2000, 19 July 2001, 26 July 2001 and 19 August 2001 made by the Petitioners relating to the enhancement of the vessel charges and pass appropriate orders. The points made by AIFI to VPT in its letter dated 2 May 2018 about one time settlement proposals for clearing the berth hire charges of their respective Fishing boats does not relate to the matter directed by the Hon'ble High Court to this Authority and hence do not form part of this proceedings. In any case the letter is addressed to VPT and does not seek anything from this Authority as such. The VPT has stated that the matter is under examination by the port.

19. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the representations of the Petitioners dated 09.12.2000, 19.07.2001, 26.07.2001 and 18.8.2001 in compliance with the common Order dated 20 December 2017 of the Hon'ble High Court endorsing the decisions taken by the VPT on the matter.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./194/18]